उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ।

टावर–4 प्रथम/द्वितीय तल, सिग्नेचर भवन पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, लखनऊ–226010

पत्रांकःएफएस–1505–2020(2) दिनांकः जून , 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः निर्देश याचिका सं0 862/2020 अभयभान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के निर्णय के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 की आख्या व तदनुसार शासकीय निर्देश निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

—

कृपया निर्देश याचिका सं0 862/2020 अभयभान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिए गये आदेश/निर्णय दिनांक 17.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सन्दर्भित निर्णय के प्रस्तर–12 से 17 तक में अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 6 व 7 व अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली के नियम 3 सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसके कुछ प्रस्तर निम्नवत उद्धरत हैः–

12- Under section 6 of the Act, Chief fire officer has a discretion to inspect the building and ensure the adcquacy of fire prevcntion and fire safety measures Moreover height of hotel in question was below 15 meters, as such petitioner could not be held responsible for non observance of section 6 of the Act.

13- Section 7 of the act 2005 contemplates for taking NOC/Permission from the entity/institution authorized by the state government by owner of building .Section 7 of the Act is being reproduced below-7(1) Every building above 15 meter in height whether existiong or to be erected or likely to be used for a purpose such as medical or other treatment or care of person suffering from physical or mental illness,diseases or infirmity, case of infacts, convalescents or aged person or for penal or correctional detention in which the liberty of inmetes is restcrited, shop, market, sleeping, accommodation, hotel or rooming house, educational institution, assembly building where group of people congregate or gather for amusment recreation, social, religious, patriotic, civil travels or for a similar purposes shall submit plan and obtain a permission from entity authorised by the State Government that safety from fire is reasonably attainable in practical and can be achieved.

14- Rule 3 of U.P. Fire Prevention and Fire safety rules 2005 provides that the height of the building for purpose of sub-section(1) of section 3 of the Act shall be above 15 meters.

15- Rules have been framed under the Act, Which provides that no objection certificate is essential for the building above 15 meters height,

It is admitted case that building in question was less than 15 meters height as such technically, no objection certificate was not required However renewal of no objection certificate was given by petitioner after inspection of building by the then Fire Station Officer, on the basis of his report dated 19-02-2016. Thus it is clear that petitioner has not violated any provision of law.

16- In exercise of power under section 17 of U.P. Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005 Rules have been framed Rule 2 provides that entity authority shall include local authority development authority. Municipality, Municipal Corporation Awas Vikas Parishad or Building Plan Sanctioning Authority.

Rule 3 is relevant, which is reproduced below-

"The height of the building for purposes of sub-section(1) of Section 3 of the Act shall be above 15 meters."

17- From the above, it is manifest that inspection of the building has to be made essentially if height of the building is above 15 meters.

निर्णय के उपरोक्त प्रस्तर–17 में विशेषतः यह स्पष्ट किया गया है कि उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005 व उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली 2005 के अर्न्तगत भवनो का निरीक्षण केवल 15 मीटर के ऊँचे भवनों पर ही लागू किया जाना है।

इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–18/छः–पु–08–2022/905 (34)/2016टीसी, दिनांकः 07.01.2022 में भी 15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को आवेदक की अनुशंसानुसार पूर्णतया स्वैच्छिक रखा गया है।

अतएव मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण/मा0उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों **(छायाप्रति संलग्न)** निर्णय के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम की परिधि में आने वाले भवनों हेतु स्पष्ट शासकीय दिशा–निर्देश जारी किये जाने की महती आवश्यकता है जिससे कि अग्निशमन सेवा के अर्न्तगत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम से आधिकृत अधिकारी तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही कर सके।

संलग्नकःयथोक्त।

11/6/22

(अविनाश चन्द्र)
पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।